सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERSTANDING

कार्यवाही-का सारांश

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): मैं भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा गन्धक के आयात के लिये मैसर्स ओवल इण्डस्ट्रीज, न्यूयार्क, के साथ किये गये करार के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के पांचवे प्रतिवेदन से संबंधित बैठकों के कार्य-वाही-सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

तेइसवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तेइसवे प्रतिवेदन की एक एक प्रति सभा पटल पर उपस्थित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

सैंतिसवा तथा चवालीसवा प्रतिवेदन

श्री पं० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं निम्न की एक एक प्रति सभा पटल पर उपस्थित करता हूं:—

(1) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग)—केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्था, बैरकपुर—के बारे में सैंतीसवां प्रतिवेदन।

(2) रेलवे मंत्रालय—दक्षिण पूर्व रेलवे —के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के इकानब्बे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में चवालीसवां प्रतिवेदन।

मारीशस द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त किये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re: ATTAINMENT OF INDEPENDENCE BY MAURITICUS

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि सभा मारीशस को जिसे अब स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, बधाई देने में मेरे साथ है। हमारे राज्य मंत्री श्री भगत इस समय वहां गये हुए हैं। उन्हें अब उपनिवेश-

वाद से मुक्ति प्राप्त हो गयी है। हम वहां के लोगों की खुशहाली और सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की कामना करते हैं। और मुझे आशा है कि हमारे बीच पारस्परिक सद्भावना बढ़ेगी।

सदन की ओर से मेरा आप से अनुरोध है कि आप मारीशस के लोगों तथा सरकार को हमारी शुभकामनाएं प्रेषित कर ।

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : इस बजट से लोगों में आत्मविश्वास और आशा की भावना जागृत हो गई है। उन्होंने इस बजट के प्रस्तावों का स्वागत किया है। अगले वर्ष सरकार को जो राजस्व प्राप्त हो गया वह वर्ष 1947 में सरकार को प्राप्त हुए राजस्व की तुलना में 10 गुना है। इससे हमारे देश की पिछले 20 वर्षों की प्रगति की एक झलक मिलती है।

इस वर्ष के बजट में आंध्र प्रदेश के लिये बहुत कम व्यवस्था की गई है। इससे हमारे राज्य को बहुत हानि होगी। हमने इस बारे में एक ज्ञापन प्रधान मंत्री को दिया है। मुझे आशा है उप प्रधान मंत्री हमें अवश्य कुछ सहायता देंगे।

इस बजट में दो बात ऐसी हैं कि जिनके बारे में मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता नहीं। एक तो पोस्ट कार्डों की दर बढ़ाना ठीक नहीं है। इस से देश के निम्न वर्ग के लोगों पर बोझ पड़ेगा। आपको वाणिज्य प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाया जाने वाला एक अलग कार्ड चालू करना चाहिये। उस कार्ड की दर आप सामान्य कार्ड से अधिक रख सकते हैं। इस प्रकार निर्धन जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा। आप फोनोग्राम की दर बढ़ा सकते हैं। इससे भी निम्न वर्ग पर बोझ नहीं पड़ेगा। और सरकार की आय में भी पर्याप्त वृद्धि हो जायेगी। पोस्टकार्ड के कारण हो रही हानि पूरी हो जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर हमारा लगभग 25,00 करोड़ रुपया लगा हुआ है। बहुत से उद्योगों को स्थापित हुए दस से बारह वर्ष तक हो चुके हैं। हमने विदेशों से बढ़िया मशीनरी भी मंगायी है। हमारे देश के कारीगर जब विदेशों में जाते हैं तो उन्हें वहां बहुत अच्छा वेतन मिलता है। हमें अपने देश में अच्छे वेतन देने की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि देश में औद्योगिक प्रगति हो सके।

मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी दी जानी चाहिये ताकि वे अधिक उत्पादन कर सके। इस समय मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है। माननीय मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि कृषि को प्राथमिकता दी गई है। आंध्र प्रदेश में उद्योग बहुत कम और अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। मुझे खेद है कि इस राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बहुत कम धन की व्यवस्था की गई है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि एक संसदीय समिति का गठन करें जो कि राज्यों को दिये जाने वाले धन के व्यय किये जाने तथा प्रयोग में लाने के प्रश्न पर विचार करें। रेलवे के कार्य में भी अब पहले जैसी दक्षता नहीं रही है।

श्री हेम बरूआ (मंगलदाई) : हमारे देश की इस समय की अर्थ व्यवस्था की हालत शोचनीय है। उसी का प्रतिबिम्ब हमें इस बजट में मिलता है। देश में उत्पादन कम हुआ है और मूल्यों में वृद्धि हो गयी है।